where the position of minorities is very bad and what steps Bangladesh government have taken to see that their people do not come into India and their grievances are removed? Thirdly, whether any person has been arrested on security reasons and what are the charges? How many new check posts have been created in that region and what is the strength of the Border Security Force and by how much it has been increased? Have you received any report from the Governor also?

श्री धनिक लाल मंडल : कारण जो रहे हैं वे सब को मालूम हैं । पहला यह है कि देश का बटवारा हुआ और उस के बाद जो चीजें बटवारे पर होती हैं सब हुई । उसके बाद 1971 में आजादी की लड़ाई हुई और उस आजादी की लड़ाई से जो चीजें निकलती हैं वे निक तीसरे जैसे आप ने कहा है सोशो इकोनोमिक कारण हैं, वे भी हैं । सब का मैंने जिक्र किया है अपने उत्तर में ।

प्रो० समर गुहा : पोलिटिकल रीजन भी हैं ।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं मानता हूं वे भी हैं । उन को भी हम नजरअन्दाज नहीं कर रहे हैं । आप ने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि चीफ मिनिस्टर से आप की क्या बातचीत हुई है और उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं । अलग अलग राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं । असम के मुख्य मंत्री ने कुछ सुझाव दिए हैं जैस उन्होने कहा है कि उनको इजाजत मिलनी चाहिये दो बटालियन और स्टेट आर्म्स फोर्स रिक्रूट करने की और रोविंग पैट्रोल पार्टी को करने की इजाजत होनी चाहिये और पूरा खर्चकेन्द्र उठाए । त्रिपुरा की सरकार ने कहा है कि उनको एक बटालियन और बी एस एफ की रिक्रूट करने की इजाजत मिलनी चाहिये । इस तरह से इन सब सुझावों पर विचार हो रहा है–

श्री वसंत साठे : विचार ही करते रहेंगे पांच साल तक । आचार करो, विचार नहीं ।

श्री धनिक लाल मंडल : इस मामले प बातचीत भी हो रही है । जैसे जो मोगा ट्राइबज के लोग आ गए हैं त्रिपुरा में उनको बंगला देश की सरकार की सहमति से, एग्रीमेंट से वहां से भेजा गया है । चकमा लोग मिजोरम में आ गए थे उनको बंगला देश की सरकार से एग्रीमेंट करके भेजा गया है ।

प्रो० समर गुहा : कितने भेजे गए हैं और अभी तक कितने रह गए हैं ? क्यों आए हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : क्यों आए हैं आप सब जानते हैं । अलग अलग कारण हैं । सारे मैंने एन्यूमरेट किए हैं ।

बंगला देश की जो बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और हमारी जो है समय-समय पर उन दोनों के बीच बातचीत होती रहती है इस समस्या को हल करने के लिए सरकार के स्तर पर जो होती है उससे यह अलग है । वहां भी ये सब बातें उनके ध्यान में लाई जाती हैं और इनको ठीक किया जाता है ।

जो बी एस एफ है उस में 449 पोस्ट्स हैं और 21 बटालियंन बी एस एफ की लगी हुई हैं । उसके अतिरिक्त सोलह होम गार्ड की हैं । ये उनकी मदद करती हैं । यह बहुत बड़ा बोर्डर है । इसके अतिरिक्त जो सैकिड चैक पोस्ट बनाई गई है, फर्स्ट जो बार्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके अन्दर दूसरी है जिस को पी आई बी डी कहते हैं और इस सैकिड के तहत भी सोलह सौ कुछ सैकिड पोस्ट्स हैं । सारी असम के लिए हैं । इस के अतिरिक्त मेघालय के लिए भी हैं ।

आपने यह भी पूछा है कि सिक्योरिटी एरेस्ट कोई हुई है ? सिक्योरिटी एरेस्ट अभी नहीं हुई हैं ।

MR. SPEAKER: Now, Report of the Public Accounts Comittee. Shri P. V. Narasimha Rao.

(Interruptions) **

MR. SPEAKER: After he has placed the Report on the Table. Not now. If you have given notice, I will allow you. You have not given notice. No. no. Don't record.

(Interruptions) **

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND THIRTEENTH REPORT

SHRI P. V. NARASIMHA RAO (Hanamkonda): Mr. Speaker, Sir, I beg to present the Hundured and thirteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Eighteenth Report on Road Development during Fourth Plan.

(Interruptions) **

MR. SPEAKER: That question has been answered. You must know the Procedure on Calling Attention. Don't record.

(Interruptions) **

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति आइटम नम्बर 6 पर है । मुझको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिर्फ अंग्रेजी में ही यह रिपोर्ट पेश की जा रही है । इसकी कापी हम लोगों को तत्काल हिन्दी में नहीं मिलेगी । और आपने इसी सदन में कई बार रूलिंग दी है, आप हिन्दी को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं भी दें तो कम से कम हिन्दी और

**Not recorded.

[राम विलास पासवान]

अंग्रेजी साथ साथ चलेगी। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी में ही रिपोर्ट पेश की जा रही है या उसका हिन्दी वर्जन भी हमें मिल रहा है? यदि नहीं, तो हम रिपोर्ट को आप तत्काल बन्द कीजिये, पहले इसकी हिन्दी कापी हमें दिलाइये।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा): अध्यक्ष जी,...

MR. SPEAKER: You have not given notice. You must give notice.

श्री मनीराम बागड़ी: कोई जरूरत नहीं है नोटिस देने की जब आप संविधान को बन्द कर रहे हो। आप कोई तानाशाह नहीं हो। आप भारत के संविधान को भंग कर रहे हो, अंग्रेजी भाषा को थोप रहे हो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आप भारत मां की जबान को काट रहे हो, अंग्रेजियत लाद रहे हो। आप बार-बार हमारे दिलों को ठेस पहुंचाते हो।...

MR. SPEAKER. Copy will be placed. Matters under Rule 377, Shri Kanwar Lal Gupta.

श्री मनीराम बागड़ी: यह बात नहीं चलेगी।

MR. SPEAKER: The General Purposes Committee have gone into it. No further recording please.

*(Interruptions)***

That matter was brought up. The General Purposes Committee went into the matter and they said it is not possible always.

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, हमारी आपत्ति का आपने क्या जवाब दिया? यदि हिन्दी में रिपोर्ट आती तो अंग्रेजी वाले अभी क्या करते? यह कोई साधारण बात नहीं है।

MR. SPEAKER: No further recording please. Only matters under Rule 377. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)***

12.45 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Reported copying in examinations of Meerut University and other places.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Mr. Speaker, Sir, I rise to make a statement under Rule 377 on the following matter of urgent public importance.

That copying in the examinations of Meerut University in some parts of Western U.P. has been going on, on a massive scale. Answers are being copied verbatim from the text books and handy guides. Those unfamiliar with the contents of the books bring their friends to locate the answer or higher competent people to do the job for them in the examination hall. Even the law students have been engaging qualified advocates to write their papers. The only sufferers are the girl students. The invigilators are threatened with dire consequences and are shown daggers etc. Consequently, they cannot stop this unfair practice.

Even the senior Superintendent of Examinations of some colleges of Meerut have addressed letters to the Vice-Chancellor, Meerut University in which they say that even after their best efforts they were unable to conduct the examinations fairly according to the University rules. Unfair means were being used openly *en masse* by open declarations by some students that the candidates should copy fearlessly. They have further stated that they were completely helpless and are frightened as a result of threats and that serious consequences are bound to follow if no action is taken against any student. They requested the Vice-Chancellor to take some serious action to meet the situation. Many other communications have been sent by about 50 invigilators showing their helplessness in the matter. The leading national dailies have reported extensively over this issue, but no effective steps have been taken so far. Unfortunately, the Vice-Chancellor of Meerut University has called it a minor incident. According to him, this is all exaggeration. In 13 colleges, the examinations have been cancelled —now I am told that all the examinations have been cancelled—and these will be held later on.

**Not recorded.